

नई शिक्षा नीति— 2020 में भाषा एवं पाठ्यक्रम

प्राप्ति: 20.12.2022
स्वीकृत: 26.12.2022

101

वैशाली तोमर
शोधार्थी

सन राइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान
ईमेल: tomarvaishali67@gmail.com

सारांश

साल 2020 पूरे विश्व के लिये बहुत की दुखदायी रहा क्योंकि कोविड-19 महामारी ने सम्पूर्ण मानव जाति को प्रभावित किया। भारत में इस महामारी के चलते एक विशेष परिवर्तन देखने को मिला, वह था नई शिक्षा नीति 2020 का विकास। 1986 में लागू हुई शिक्षा नीति के बाद भारत सरकार का शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। शिक्षा ध्येय ऐसे सक्रिय और सार्थक नागरिक तैयार करना है जो हमारे संविधान में निहित तत्वों के अनुरूप समतापूर्ण समावेशी तथा बहुलतावादी समाज के निर्माण में योगदान कर सकें।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिये व्यक्ति का विकास समाज के अनुसार होना चाहिए। इसलिये हमें सामाजिक मूल्यों एवं सिद्धान्तों को अपनी शिक्षा में स्थान अवश्य देना चाहिए। शिक्षा मनुष्य के चरित्र को पवित्र व सुन्दर बनाती है। यह सब कुछ निर्भर करता है शिक्षा नीति पर। शिक्षा नीति जितनी सशक्त व दूर दृष्टियुक्त होगी वह राष्ट्र उतना विकास करेगा। नई शिक्षा नीति शिक्षा में बुनियादी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के परिवर्तनों के बारे में कथनी की तुलना में करनी को महत्व देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिये नवीन शिक्षा केन्द्रों की स्थापना पर बल देती है।

यह शोध पत्र मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति-2020 में भाषा एवं पाठ्यक्रम पर केन्द्रित है। इस शोध में गुणात्मक डेटा का प्रयोग किया गया है। इस शोध पत्र के द्वारा यह पता लगाना है कि NEP-2020 से परिवर्तित भाषा एवं पाठ्यक्रम नयी पीढ़ी के लिये कितना प्रभावी एवं लाभकारी है।

मुख्य बिन्दु

कोविड-19 महामारी, नई शिक्षा नीति 2020, ध्येय, सक्रिय, सार्थक, समावेशी, बहुलतावादी, मूल्यों, संशक्त, बुनियादी, धारा, भाषा, पाठ्यक्रम, गुणात्मक, डेटा, परिवर्तित, लाभकारी।

प्रस्तावना

शिक्षा का उददेश्य मानव को ऐसा इंसान बनाना है जिसकी सोच और कार्य युक्तिसंगत हो, जिसमें दया और सहानुभूति हो, साहस एवं संकटों का सामना करने की क्षमता हो, वैज्ञानिक दृष्टीकोण हो तथा नैतिकता एवं मूल्यों के साथ रचनात्मक कल्पना शक्ति हो। वर्तमान में आयी नई शिक्षा

नीति—2020 शिक्षा के इन सभी उददेश्य को पूरा करने में संकल्पबद्ध है NEP-2020 के आने के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में भी 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलावों का अहम सिलसिला शुरू हो गया है।

भारत में सबसे पहले 1968 में नई शिक्षा नीति बनायी गयी थी उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में नई शिक्षा नीति बनायी गयी थी। जिसे 1992 में फिर से संशोधित किया गया था। लगभग 34 वर्षों बाद 2020 में NEP को लाकर बड़े बदलाव किये गये हैं। नई शिक्षा नीति—2020 29 जुलाई 2020 को लागू की गयी। इसका निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2015 के दिन आरम्भ हुआ। तत्कालीन सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में पाँच सदस्यों की कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को सौंपी। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख रहे वैज्ञानिक डा० के कस्टरीरिंगन की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की कमेटी को NEP का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट एच.आर.डी. मंत्री रमेश पोखरियाल निंशक को सौंपा गया। इस पर दो लाख से ज्यादा सुझाव आए और इसके बाद 29 जुलाई 2020 के केन्द्रीय कैबिनेट ने NEP के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। मानव संसाधन प्रबन्ध मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। नई शिक्षा नीति का उददेश्य—शिक्षा के स्तर में सुधार कर शिक्षा नीति की गुणवत्ता को बढ़ाना, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करना तथा स्कूल के बुनियादी ढाँचे का विकास और नवीन शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना है।

NEP में 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून—2009 के अन्तर्गत रखा गया है। 1986 की के NEP 10+12 के मॉडल के स्थान पर अब 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को बाँटा गया है। NEP 2020 के लिये सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिये देश की 6 प्रतिशत जीडीपी के बराबर शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करेगी। इस नीति में शिक्षा तक सबकी पहुँच सभी की भागीदारी और शिक्षण स्तर के मामले में विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस नीति में समानता को ही समावेशी व्यवस्था का आधार माना गया है।

उददेश्य

इस शोध पत्र का प्रमुख उददेश्य नई शिक्षा नीति 2020 में परिवर्तित भाषा एवं पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर उसके बारे में सही एवं सटीक जानकारी प्रदान करना है जिसमें पाठक लाभान्वित हो सके।

अनुसंधान क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीय आँकड़े पर आधारित है। यह आँकड़े मानव संसाधन प्रबन्ध मंत्रालय की वेबसाइट से समाचार पत्रों, शोध पत्रों, हाईकवर पुस्तक एवं जर्नल और आनलाइन पत्रिकाओं आदि से पुनः प्राप्त किये गये हैं। गूगल स्कालर पर भी ऑनलाइन पत्रिकाओं की खोज की गई। इस शोध पत्र में गुणात्मक डेटा का प्रयोग किया गया है। जिसमें वर्णनात्मक अवलोकन एवं ऐतिहासिक विधियों का प्रयोग किया गया है।

नई शिक्षा नीति में संरचनात्मक परिवर्तन

(क) स्कूल शिक्षा संबंधी प्रावधान—नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 के फॉर्मूले को प्रस्तावित किया गया है जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा दी जाएगी। इसमें 3 से 18 साल तक की आयु वाले बच्चों को शामिल किया जायेगा। इस शिक्षा के चार चरण होंगे जो निम्न प्रकार हैं:—

1. फाउडेशन स्टेज / बुनियादी चरण:- इसमें 3 से 8 साल तक बच्चे अध्ययन करेंगे। जिसमें 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूली शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा कक्षा 1 व 2 शामिल होंगी। इसमें बच्चों को भाषा कौशल और शिक्षण के विकास का ज्ञान दिया जायेगा।
 2. प्रीपेटरी/प्राथमिक चरण:- इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चों को शामिल किया जायेगा। जो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक अध्ययन करेंगे। जिनको भाषा एवं संख्यात्मक कौशल का ज्ञान दिया जायेगा।
 3. मिडिल/उच्च प्राथमिक चरण:- यह चरण कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिये होगा। इस स्टेज में बच्चों को कोडिंग व्यवसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, प्रशिक्षण दिया जायेगा।
 4. सेकेन्डरी/माध्यमिक चरण:- इस स्टेज में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को शामिल किया गया है। इसमें वह वैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है।
- (ख) उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान:- नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा से संबंधित निम्न परिवर्तन किये गये हैं जो इस प्रकार हैं:-
1. स्नातक / बीए० की 3 वर्ष की डिग्री अब NEP 2020 के तहत 4 वर्ष की होगी। प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
 - वर्ष की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जायेगा।
 - 2 वर्ष के बाद ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
 - 3 वर्ष के बाद ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी।
 - 4 वर्ष का स्नातक करने वाले को रिसर्च यानि शोध ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
 2. परास्नातक / पीजी 1 या 2 वर्ष का होगा।
 - अगर किसी ने 3 वर्ष का स्नातक डिग्री कोर्स किया है तो उसे 2 वर्ष का स्नातकोत्तर करना होगा।
 - केवल 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वालों को ही 1 वर्षीय स्नातकोत्तर में प्रवेश मिलेगा।
 3. 2020 की नयी शिक्षा नीति के तहत Ph.D कुल चार वर्ष की होगी। अब एम०फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।
 - 4- NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 5 प्रतिशत तक करने के लक्ष्य रखा गया है। तथा देश के उच्च शिक्षण संस्था में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
 5. 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टीडिसिप्लीनरी बनाया जायेगा। पाली, प्राकृत, पर्सियन के लिये यूनिवर्सिटी कैंपसों में ही राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किये जायेंगे।

NEP 2020 में भाषा का प्रारूप

दुनिया भर के अनुभव इस बात के गवाह है। कि किसी देश के लिये देश में बदलाव के लिये शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण औजार है और हर शिक्षा का वाहन भाषा होती है। 29 जुलाई 2020 में घोषित हुई नई शिक्षा नीति कई सरकारी पड़ावों से गुजरती हुई अब रप्तार ले रही हैं। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना वर्तमान केन्द्र सरकार की प्राथमिकता रही है। आजादी के बाद से 2014 तक, सिर्फ अंग्रेजी ही देश की शिक्षा को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे भ्रम या मिथक को बढ़ावा दिया जाता रहा। उसके प्रमाण हैं देश भर में कई गुना रप्तार से बढ़ते अंग्रेजी माध्यम स्कूल।

लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा— मातृभाषा, स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से दिये जाने पर बल दिया गया है। यदि संभव हो और कोशिश की जानी चाहिए कि आठवीं तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं और मातृभाषाओं में हो। अंग्रेजी मात्र एक विषय के रूप में ही पढ़ाई जाए, माध्यम भाषा के रूप में नहीं। उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी को अभी छूट दी गयी है और वह इसलिये कि आने वाले दिनों में धीरे—धीरे भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तक और सामग्री उपलब्ध हो जायेगी। तो वहाँ भी भारतीय भाषाओं को लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में सभी भाषा व बोलियों का सम्मान है इसलिये इस नीति में मातृभाषाओं और स्थानीय भाषाओं दोनों को जगह दी गई है। शिक्षक पढ़ाते समय वहाँ की स्थानीय भाषा, शब्द परंपरा, लोक कथा आदि को साथ रखते हुये बच्चों के बीच संवाद करेगा, तो वे रटने की प्रवृत्ति से तो दूर होंगे। उन्हे पढ़ने में भी आनन्द आएगा और यही NEP का मूल मंत्र है। इसलिये दुनिया भर में प्राथमिक शिक्षा विशेष रूप से अपनी भाषाओं में कराने की वकालत की गई है और संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी इसी बात को धूनेस्व आदि के माध्य से दुनिया भर को बताया जाता है।

नई शिक्षा नीति में भाषा को लेकर निम्नपरिवर्तन किये गये हैं। जो निम्न प्रकार है:—

- इस शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के रूप में अपनाने पर बल दिया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं जैसे प्राकृत पालि आदि का विकल्प उपलब्ध होगा।
- विदेशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। छात्र अपनी इच्छानुसार इनका अध्ययन कर सकते हैं इसके लिये उन्हे बाध्य नहीं किया जाएगा।
- NEP 2020 शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के प्रयोग पर बल देती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारतीय भाषाओं को रोजगार के अवसरों के लिये योग्यता के मानदण्डों में शामिल किया जायेगा।
- NEP 2020 के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान फारसी, प्राकृत और पालि के लिये राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने के लिये मातृभाषा या स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया है।

नई शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम का प्रारूप

नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के साथ ही पठन—पाठन की शिक्षार्थी केन्द्रित व्यवस्था लाने के नए प्रतिमान अपनाने पर विचार होने लगा है। जिसके तहत छात्रों की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर ध्यान देकर उनका समग्र और सर्वांगीण विकास हो सकेगा। NEP 2020 में शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षरज्ञान और अंकज्ञान विवेचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान तक ही सीमित न रहकर सामाजिक और भावनात्मक कौशल को विकसित करना भी है। जिन्हें सापेट स्किल कहते हैं। इसलिये नई शिक्षा नीति में वोकेशनल (कौशल) पढ़ाई पर मुख्य जोर दिया गया है।

NEP 2020 में पाठ्यक्रम में निम्न परिवर्तन किये गये हैं जो इस प्रकार है:—

- इसमें स्कूल शिक्षा के लिये नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम व्यवस्था अपनाने की व्यवस्था की गई है। जैसे— 5+3+3+4

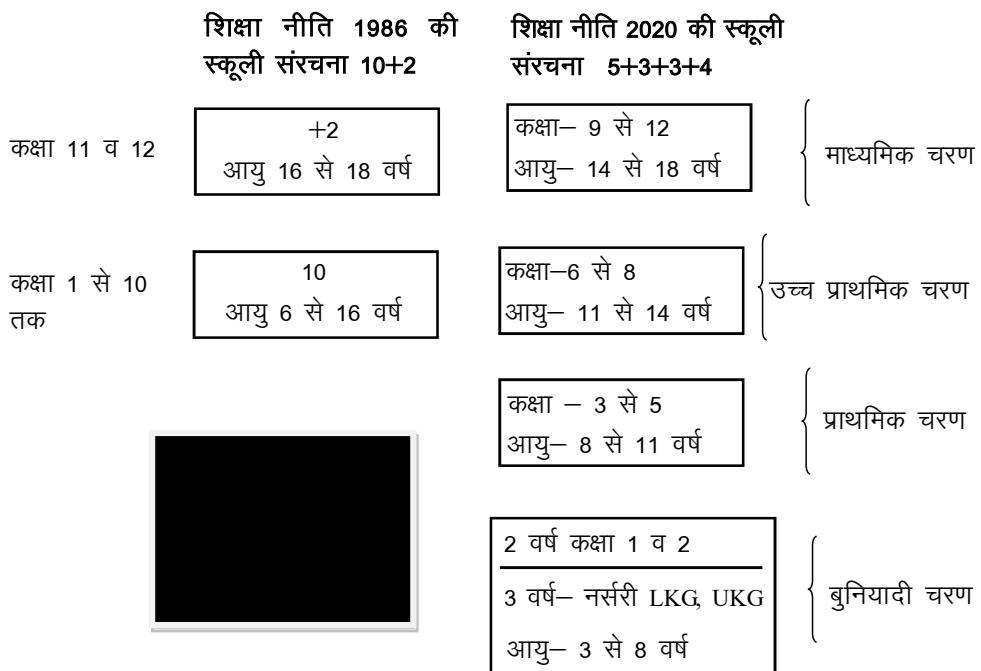
- बुनियादी चरणः— 3 से 8 साल तक के कक्षा—2 तक के बच्चों को बहु स्तरीय खेल/गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जायेगा।
- प्रारंभिक चरणः— कक्षा 3 से 5 तक जिसमें खेलकूद नई खोजें, गतिविधि—आधारित और कक्षा में परस्पर चर्चा के माध्यम से सिखाया जायेगा।
- मध्य चरणः— कक्षा 6 से 8 तक विज्ञान, गणित कला और समाजशास्त्र की अनुभवजन्य शिक्षा प्रदान की जायेगी। कौशल शिक्षा पर मुख्य जोर दिया गया है।
- माध्यमिक चरणः— कक्षा 9 से 12 तक विभिन्न विषयों की पढ़ाई के साथ विवेचनात्मक सोच लचीलेपन और विषयों के विकल्प की व्यवस्था भी रहेगी।
- NEP 2020 में वोकेशनल शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। इसमें बागवानी मिटटी के बर्तन बनाना, बिजली का काम, लकड़ी का काम, योग, नृत्य, संगीत, कला, खेल आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पढ़ाई कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को कराई जाएगी। इन छात्रों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ—साथ व्यवसाय इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किये जायेंगे।
- माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं में बदलाव किया जायेगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्प प्रश्न आदि को शामिल किया जा सकता है।
- माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 में स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी बल्कि मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। रसायनशास्त्र का छात्र चाहे तो भूगोल भी पढ़ सकता है या कोई अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि जैसे— संगीत या कोई खेल है तो उसे भी एक विषय के रूप में चयन कर सकता है।
- स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव किये जायेंगे। पुस्तकों एवं सामाग्री को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में निर्मित किया जायेगा।
- उच्च स्तर पर अब छात्रों के लिये कई तरह के विकल्प होंगे।
- बी0ए0, बी0एस0सी0 जैसे ग्रेजुएशन कोर्स अब 4 सल के होंगे। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिये 4 साल का ग्रेजुएशन होगा।
- 4 साल के ग्रेजुएशन वालों के लिये पीजी—1 वर्ष का होगा तथा 3 साल के बी0ए0 वालों के लिये पीजी—2 साल का होगा।
- 4 साल के ग्रेजुएशन वालों के लिसे पी0एच0डी0 4 साल की होगी। NEP 2020 में एम0फिल को खत्म कर दिया गया है।
- शिक्षक बनने के लिये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी0एड0 डिग्री का होना अनिवार्य होगा। NCERT की सलाह से NCTE टीचर्स ट्रेनिंग के लिये एक नया पाठ्यक्रम NCFTE 2021 तैयार करेगा।
- कालेज और विश्व विद्यालयों को समान बनाते हुए बहुविषयक पाठ्यचर्या लागू की जायेगी कला, विज्ञान, तथा वाणिज्य सभी विषय समिलित रूप से पढ़ाये जायेंगे।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

NEP 1986 एवं NEP 2020 के भाषा व पाठ्यक्रम में अन्तरः—

पहले जहाँ शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाया जाता था। उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 1986 एवं नई शिक्षा नीति 2020 दोनों का अध्ययन करने पर दोनों में अनेक अन्तर पाये गये हैं जो निम्न हैं:-

1. NEP 1986 की तुलना में NEP 2020 अत्यन्त व्यापक, लचीली और संकल्प बद्ध है।
2. नई शिक्षा नीति-1986 में स्कूली शिक्षा का प्रारूप 10+2 का होता था जबकि नई शिक्षा नीति 2020 में इस प्रारूप को बदलकर नया प्रारूप 5+3+3+4 कर दिया गया है।
3. NEP 1986 में बच्चे की शिक्षा कक्षा 1 से एवं 6 वर्ष की अवस्था में शुरू होती थी जबकि NEP 2020 में 3 साल का बच्चा नर्सरी से अपनी शिक्षा प्रारम्भ करेगा।
4. NEP 2020 में कक्षा 6 से बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी परन्तु NEP 1986 में व्यवसायिक शिक्षा +2 अर्थात् उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाती थी।
5. NEP 1986 में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया था जिसमें तीन भाषाओं— हिन्दी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया था। कोई भी राज्य अपने क्षेत्र के अनुसार अपनी भाषा को चुन सकता था। जबकि NEP 2020 में अंग्रेजी को विशेष भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। कक्षा 6 से अंग्रेजी मात्र एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होगा।
6. NEP 1986 में माध्यमिक स्तर पर गाणित व विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था जबकि NEP 2020 में शिक्षा प्रणाली बहुविषयक एवं वैकल्पिक होगी। अब छात्र अपनी इच्छा से कोई भी विषय चुन सकता है। अगर साइंस का छात्र भूगोल या कोमर्स लेना चाहे तो वह स्वतन्त्र है वह साइंस स्ट्रीम के साथ-साथ अब आर्ट्स स्ट्रीम के विषय भी पढ़ सकता है।
7. NEP 1986 में बोर्ड परीक्षाओं को सार्वजनिक तौर पर सैद्धान्तिक रूप से कराने सतत मूल्यांकन और अक्षर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है। जबकि NEP 2020 में साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएँ कराई जाने की बात कही गई है। परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र बनाने पर जोर दिया जाएगा। तथा मूल्यांकन स्वयं छात्र द्वारा सहपाठियों द्वारा व अभिभावकों के द्वारा भी किया जाएगा। छात्र की गतिविधियों के आधार पर भी अध्यापक उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के लिये परख नाम संस्थान का नियोजन किया जाएगा।
8. NEP 1986 में बी0ए0 3 वर्ष का व पी0जी0 2 वर्ष के होते थे। परन्तु अब NEP 1986 में बी0ए0 4 वर्ष व पी0जी0 1 या 2 वर्ष का होगा। जो शोध कार्य में जाना चाहते हैं उन्हें 4 वर्ष का बी0ए0 करने के बाद 1 वर्ष का पी0जी0 करना होगा। उनके लिये पी0एच0डी0 4 वर्ष की होगी। NEP 2020 में एम0फिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है जबकि NEP 1986 में एम0फिल को मान्यता प्राप्त थी।
9. NEP 1986 में प्राथमिक विद्यालयों के लिये ब्लैक बोर्ड योजन तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिये नवोदय विद्यालय की स्थापना की गयी थी। परन्तु NEP 2020 में ऐसी किसी योजना को लागू नहीं किया गया है।
10. मैडिकल की पढ़ाई के लिये जो नीट परीक्षा पहले सिर्फ अंग्रेजी में होती थी वह अब तेरह भारतीय भाषाओं में शुरू हो गई है। कक्षा 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाएँ हैं और NEP 2020 के माध्यम से यह प्रयास है कि सभी भाषाओं में इसे समान रूप से लागू किया जाए।

11. पहले शिक्षक भर्ती के लिये बी0एड0 एवं बीटीसी अनिवार्य होता था परन्तु अब NEP 2020 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी0एड0 के साथ टी0ई0टी0 पास होना अनिवार्य है।



NEP 1986 एवं NEP 2020 की तुलनात्मक संरचना प्रणाली

समीक्षा एवं सुझाव

नई शिक्षा नीति 2020 छात्रों के बीच नये विचारों के समावेश के साथ सहभागिता महत्वपूर्ण सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करती है। यह शिक्षा नीति अपनी मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने का अधिकार प्रदान करती है। यह नीति सीखने वाले की आत्म क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल पर जो देती है तथा बच्चों को अपनी प्रतिभा विकसित करने में मदद करेगी। पहले छात्रों के पास अध्ययन के लिये केवल एक ही विषय चुनने का विकल्प था लेकिन अब छात्र अलग अलग विषय चुन सकते हैं। इस शिक्षा नीति में हर विषय पर समान रूप से व्यवहार करने पर जोर दिया गया है। 2030 तक सभी संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थान बहु—विषयक बन जायेंगे। NEP 2020 में वोकेशनल शिक्षा को बढ़ावा देकर छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का सफल प्रयास किया गया है। इससे देश में बेरोजगारी भी कम होगी, छात्र कौशल शिक्षा प्राप्त कर अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकेंगे। तथा साथ—साथ और व्यवित्रियों को भी रोजगार दे पायेंगे।

नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिये कुछ चुनौतियाँ हैं तथा साथ में कुछ सुझाव भी अपेक्षित हैं जो निम्न प्रकार से हैं:-

- इस नीति की सफलता जमीनी स्तर पर तथा स्कूलों में शिक्षकों पर निर्भर करती है शिक्षकों का प्रदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण निवेश है सरकार के सामने इन सभी को नई

शिक्षा नीति 2020 के बारे में शिक्षित करना सशक्त बनाना प्रशिक्षण देना और कुशल बनाना बहुत बड़ी चुनौती है।

- शिक्षण सामग्री का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती होगी। NEP 2020 बहुभाषावाद पर अधिक बल दिया गया है। स्थानीय भाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिये बहुत परिश्रम की आवश्यकता है।
- सरकार को विभिन्न संगठनों जैसे— NCERT, SCERT, स्कूल विभागों आदि से सहायता लेकर इस नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है।
- NEP 2020 में कहा गया है कि अब पाठ्यचर्चा में पाठ्यसहगामी गतिविधिया अलग नहीं होंगी। इस प्रकार की एकीकृत सामग्री का निर्माण करने के लिये अकादमिक लोगों और बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा।
- पाठ्यक्रम में न्यूनतम 20–30 प्रतिशत स्थानीय सामग्री का समावेश होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिये प्रयत्न किया जाएँ।
- क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अध्ययन करने एवं किसी भी स्तर की परीक्षा देनी की छूट होनी चाहिए।
- अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करने के लिये राष्ट्रव्यापी कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास एवं प्रसार के लिये विशेष प्रयत्न किये जाएँ।
- किसी भी स्तर की पाठ्यचर्चा में संज्ञानात्मक विकास के विषय एवं क्रियाओं के साथ—साथ भावात्मक विकास के विषयों एवं क्रियाओं को जोड़ा जाना चाहिए।
- इस नीति में शिक्षा पर भारत सरकार की जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय करने की बात कही गयी है जबकि वर्ष 2017–18 में भारत सरकार ने जीडीपी का महज 2.7 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च किया था। अतः घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिये प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

इस शोध पत्र में किये गये अध्ययन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 कई उपक्रमों के साथ रखी गई है। जो वास्तव में वर्तमान समय की जरूरत है। नीति का लक्ष्य शिक्षा में सुधार कर उसको सर्व सुलभ बनाना है तथा 2030 तक 100 प्रतिशत सफल नामांकन प्राप्त करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक है। यह नीति अपने दृष्टिकोण और इरादे में वैशिक के साथ ही स्थानीय भी है। यह कई मायनों में पिछली नीतियों से काफी आगे हैं। इसके नये सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंस्ट्रूटर, लैपटाप और फोन आदि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने पर बल दिया गया है।

कुछ मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, बहुभाषा व्यवस्था को बढ़ावा देने शोध, नवाचार, पाठ्यक्रम सुधार, टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षण विज्ञान और कुछ करने को प्रेरित करने वाली प्रतिभा विकसित करने जैसे कार्यक्रम अपनाकर सरकार ने स्कूल शिक्षा में बदला लाने का अपना संकल्प व्यक्त किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि वह देश के हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति संकल्पबद्ध है। जितनी जल्दी NEP 2020 के उद्देश्य प्राप्त होंगे उतनी ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ेगा और वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत फिर से दुनिया का विश्वगुरु बन जाएगा।

सन्दर्भ

1. भारत सरकार. (2020). नई शिक्षा नीति–2020. शिक्षा मंत्रालय: नई दिल्ली. शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट— www.education.gov.in/en. एवं [https://hi.m.wikipedia.org>wiki](https://hi.m.wikipedia.org/wiki).
2. सिंह, डा० ममता., पोखरियाल, डा० चेतना. भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एक क्रांतिकारी पहल. सत्यम पब्लिशिंग हाउस: नई दिल्ली. ISBN:- 978-81-953249-1-0.
3. लाल, प्रो० रमन बिहारी एवं शर्मा, डा० कृष्णकान्त. भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएँ. आर. लाल. बुक डिपो: मेरठ. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986. पृष्ठ 317–348.
4. योजना पत्रिका. वर्ष : 66. अंक :इ 02. फरवरी–2022. वेबसाइट— www.publicationdivision.nic.in.
5. गूगल स्कालर. <https://scholar.google.Com>.
6. <https://jagranjost.Com>national>.
7. नई शिक्षा नीति–2020 विकिपीडिया hi.m.wikipedia.org/wiki.